सं. I-34020/03/2026-समन्वय-I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

अक्टूबर, 2026 के दौरान गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियाँ, महत्वपूर्ण प्रगति एवं प्रमुख घटनाक्रम।

- भारत की माननीया राष्ट्रपति महोदया ने अक्टूबर, 2026 के महीने में निम्नलिखित विधेयकों पर सहमति दी:

i. दिनांक 13.10.2026 को- 'पंजीकरण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025'
ii. दिनांक 23.10.2026 को – 'फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2026'

- दिनांक 20.10.2026 को, 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026' अधिसूचित किया गया जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर को लागू किया था और यह दिनांक 19 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। इस संशोधन से लद्दाख के सभी 8 जिलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- दिनांक 22.10.2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सां.आ. 5751 के माध्यम से 'राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023' के तहत सभी संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई।

- दिनांक 27.10.2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना संख्या 45 के माध्यम से 'लक्षद्वीप पर्यटन व्यापार (पंजीकरण, सुरक्षा और सुविधा) विनियम, 2026' के प्रवर्तन से संबंधित अधिसूचना प्रकाशित की गई।

- अक्टूबर 2026 में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की:

i. दिनांक 13.10.2026 को – पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक। बैठक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रति, बिम्सटेक सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया।
ii. दिनांक 13.10.2026 को - नेपाल और भूटान के माननीय गृह मंत्रियों के साथ सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में बैठक।

- अक्टूबर, 2026 के महीने में, केंद्रीय गृह सचिव महोदय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की:

i. दिनांक 03.10.2026 को – मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा बैठक।
ii. दिनांक 08.10.2026 को – मुख्यमंत्री, नागालैंड द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में बैठक।
iii. दिनांक 14.10.2026 को – मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के राहत एवं पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक की अवधि के लिए मणिपुर सरकार के प्रस्तावों; तथा मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु SRE (NE) योजना के अंतर्गत CRPF एवं BSF के प्रस्तावों पर बैठक।
iv. दिनांक 16.10.2026 को - श्रीमती लिंडी कैमरन, ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ बैठक।
v. दिनांक 25.10.2026 को – मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक।

- दिनांक 15.10.2026 को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत नक्सल हिंसा के पीड़ितों सहित दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन) को सहायक उपकरण वितरित करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समारोह को संबोधित किया।

- गृह मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श करके, 'सर्वे ऑफ इंडिया' के मानचित्रों पर दर्शाने हेतु 55 स्थानों/विशेषताओं की पहचान की। इनमें 27 स्थान अरुणाचल प्रदेश में और 28 स्थान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हैं। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े पहले चरण की घोषणा दिनांक 07.10.2026 को तथा लद्दाख से जुड़े द्वितीय चरण की घोषणा दिनांक 02.10.2026 को की गई।

- प्रत्यर्पण पोर्टल, जिसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने नई दिल्ली में 'PRAHAAR – CT Policy and Strategy' सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था, अक्टूबर 2026 में सक्रिय हुआ। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विदेशी देशों से भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की स्वचालित ट्रैकिंग, सूचना साझा करने और राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टल प्रशासनिक देरी को कम करने और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखता है।

- दिनांक 14.10.2026 को, जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति (HLCDC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (सेवानिवृत्त) ने सार्वजनिक भागीदारी और वैज्ञानिक डेटा संग्रह को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक पोर्टल https://demography.mha.gov.in लॉन्च किया।

- दिनांक 23.10.2026 को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारत-म्यांमार-बांग्लादेश डेथ ट्राएंगल कॉरिडोर के माध्यम से संचालित अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 स्थानों पर एक साथ छापे मारने के लिए 38 टीमों को तैनात करते हुए 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' शुरू किया। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 18 गिरफ्तारियां हुई, 500 डेटोनेटर और ₹12 लाख नकद जब्त किए गए, हवाला लेनदेन में ₹100 करोड़ का खुलासा हुआ, 1,424 बैंक खातों को फ्रीज किया गया और ₹17.82 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गईं।

- गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नागालैंड के 9 जिलों तथा 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों, मणिपुर के संपूर्ण राज्य (5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों एवं नामसाई जिले के 3 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत दिनांक 01.10.2026 से अगले छह महीनों की अवधि के लिए पुनः 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, असम सरकार ने दिनांक 07.10.2026 की अधिसूचना के माध्यम से 3 जिलों—तिनसुकिया, चराइदेव और शिवसागर को AFSPA के तहत दिनांक 01.10.2026 से अगले छह महीनों की अवधि के लिए पुनः 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

- दिनांक 12.10.2026 को केरलम, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों के लिए 06 राज्यपालों की नियुक्ति की गई।

- दिनांक 28.10.2026 को, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक तीव्र चक्रवाती तूफान 'अर्नब' विकसित हुआ और विशाखापत्तनम और बापटला के बीच आंध्र प्रदेश तट पर 135–140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। गृह मंत्रालय के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस (ICR-ER) ने चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी की और 49 रेड-अलर्ट एडवायज़री जारी की। प्रभावित राज्यों और क्षेत्रों में कुल 39 NDRF टीमों को बचाव अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया, जिससे जानें बचाने और नुकसान को कम करने में मदद मिली।

- दिनांक 31.10.2026 को, गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलो (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनो (CPOs) के 490 कर्मियों को पुलिसिंग, अपराध जांच, विशेष अभियान और फोरेंसिक विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया।

- गृह मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने वाले तीसरे देशों के यात्रियों को निःशुल्क आधार पर अस्थायी लैंडिंग परमिट (TLP) प्रदान करने का निर्णय लिया गया, ताकि वे वहाँ से आगे भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) की यात्रा कर सकें।

***

No. I-34020/03/2026-Coord.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
***

Major Achievements, significant Development and important events of Ministry of Home Affairs during the month of October, 2026.

- In the Month of October, 2026, Hon'ble President of India assented to the following Bills:

i. On 13.10.2026 – 'Registration (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2025.'
ii. On 23.10.2026 – 'Frontier Nagaland Territorial Authority Bill, 2026.'

- On 20.10.2026, 'Ladakh Autonomous Hill Development Councils (Amendment) Regulation, 2026', was notified which had been promulgated by the Hon'ble President of India on October 16,

2026, and came into effect on October 19, 2026. This amendment paves the way for the establishment of Ladakh Autonomous Hill Development Councils (LAHDCs) in all 8 districts of Ladakh.

- On 22.10.2026, a notification regarding the delegation of powers to all UTs under the National Dental Commission Act, 2023, was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide S.O. 5751(E).

- On 27.10.2026, a notification regarding the promulgation of “The Lakshadweep Tourism Trade (Registration, Safety and Facilitation) Regulation, 2026” was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide Notification No. 45.

- In the month of October, 2026, Hon’ble Union Home Minister chaired the following important meetings:

i. On 13.10.2026 - First BIMSTEC Home Ministers’ Meeting in New Delhi. The meeting reaffirmed the shared commitment of BIMSTEC member states to strengthening regional security, trust and cooperation in the Bay of Bengal region.
ii. On 13.10.2026 – Meetings with the Hon’ble Home Ministers of Nepal and Bhutan at Sushma Swaraj Bhawan, New Delhi.

- Union Home Secretary chaired the following important meetings in the month of October, 2026:

i. On 03.10.2026 - A review meeting on important issues related to the state of Madhya Pradesh.
ii. On 08.10.2026 - A meeting regarding the issues raised by Chief Minister, Nagaland.
iii. On 14.10.2026 - A meeting on Proposals of the Government of Manipur regarding financial assistance for relief and rehabilitation of IDPs in Manipur, for FY 2025-26 to 2027-28; and on proposals of CRPF and BSF under SRE(NE) scheme for strengthening CAPF infrastructure in Manipur.
iv. On 16.10.2026- A meeting with Mrs. Lindy Cameron, British High

Commissioner.

v. On 25.10.2026 - A meeting to review the security situation in Manipur.

- On 15.10.2026, Hon'ble Union Home Minister addressed a ceremony via video conference for distributing assistive devices to Divyangjan (persons with disabilities), including victims of Naxal violence, under the ongoing 'Seva Sankalp Abhiyan'.

- Ministry of Home Affairs, in consultation with stakeholders, identified 55 places/features for plotting on Survey of India maps, comprising 27 in Arunachal Pradesh and 28 in the Union Territory of Ladakh. The first phase covering Arunachal Pradesh was announced on 7 August 2026, followed by the second phase covering Ladakh on 2 October 2026.

- The Extradition Portal, launched by the Union Home Minister during the 'PRAHAAR – CT Policy and Strategy' Conference in New Delhi, became operational in October 2026. It is a centralised digital platform designed to streamline the extradition of fugitive criminals from foreign countries through automated tracking, information sharing and coordination among State Police, Ministry of Home Affairs (MHA), Ministry of External Affairs (MEA), Central Bureau of Investigation (CBI) and other law enforcement agencies. The portal aims to reduce administrative delays and strengthen inter-agency coordination for faster extradition processes.

- On 14.10.2026, Justice Prakash Prabhakar Naolekar (Retd.), Chairman of the High-Level Committee on Demographic Changes (HLCDC), launched the official portal https://demography.mha.gov.in to promote public participation and scientific data collection.

- On 23.10.2026, Narcotics Control Bureau (NCB) launched 'Operation Trident', deploying 38 teams for simultaneous raids at 38 locations across Assam, Mizoram and Manipur to dismantle

an international drug cartel operating through the India–Myanmar–Bangladesh Death Triangle Corridor. The operation resulted in 18 arrests, seizure of 500 detonators and ₹12 lakh in cash, uncovering ₹100 crore in hawala transactions, freezing 1,424 bank accounts and attaching properties worth ₹17.82 crore.

- Vide MHA's Notification dated 24.09.2026, 9 districts and 21 Police Stations in 5 other districts of Nagaland, entire State of Manipur excluding the areas falling under the jurisdiction of 13 Police Stations and 5 districts and Tirap, Changlang and Longding districts & the areas of 3 Police Stations in Namsai districts of Arunachal Pradesh have been declared as 'disturbed areas' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) for a further period of six (6) months w.e.f. 01.10.2026. The Government of Assam declared 3 districts (Tinsukia, Charaideo & Sivasagar) as 'disturbed area' under AFSPA for a further period of six (6) months w.e.f. 01.10.2026 vide notification dated 07.10.2026.

- On 12.10.2026, 06 Governors have been appointed for the States of Keralam, Tamil Nadu, Odisha, Karnataka, Uttarakhand and Sikkim.

- On 28.10.2026, a severe cyclonic storm 'Arnab' developed over the Bay of Bengal and made landfall along the Andhra Pradesh coast between Visakhapatnam and Bapatla, with wind speeds of 135–140 kmph. The MHA's Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER) monitored the situation round the clock and issued 49 red-alert advisories. A total of 39 NDRF teams were deployed across affected states and regions to conduct rescue operations, helping save lives and minimise damage.

- On 31.10.2026, MHA awarded the 'Kendriya Grihmantri Dakshata Padak' to 490 personnel from various States, Union

Territories, entral Armed Police Forces (CAPFs) and (Central Police Organisations) CPOs for their outstanding contributions in policing, crime investigation, special operations and forensic science.

- MHA has decided to grant Temporary Landing Permit (TLP) to third country visitors arriving at Guwahati International Airport, on gratis basis, to enable them to travel onward to Gelephu Mindfulness city (GMC), Bhutan.

*****